

अध्याय - 11 | उपभोक्ता संरक्षण

QUIZ-01

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या प्रदान करता है?
- महंगा निवारण तंत्र
 - त्वरित और सस्ता निवारण
 - केवल पुलिस कार्रवाई द्वारा मुआवजा
 - निजी कंपनियों से सहायता

(B)

व्याख्या: अधिनियम उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित और सस्ते निवारण को सुनिश्चित करता है।

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन उपभोक्ता नहीं माना जाता है?
- स्वयं के उपयोग हेतु खरीदने वाला व्यक्ति
 - व्यक्तिगत उपयोग के लिए सेवा लेने वाला व्यक्ति
 - पुनः विक्रय हेतु वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति
 - खरीदार की अनुमति से सेवा का लाभ उठाने वाला

(C)

व्याख्या: अधिनियम व्यावसायिक या पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदने वालों को उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं मानता।

3. निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता का अधिकार है?
- अधिक मूल्य वसूलने का अधिकार
 - उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
 - विज्ञापन करने का अधिकार
 - करों की वापसी का अधिकार

(B)

व्याख्या: उपभोक्ता को उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार होता है ताकि वह अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों को जान सके।

4. ₹2 करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तुओं/सेवाओं से संबंधित शिकायतें किस आयोग द्वारा संभाली जाती हैं?
- जिला आयोग
 - क्षेत्रीय आयोग
 - राज्य आयोग
 - राष्ट्रीय आयोग

(D)

व्याख्या: राष्ट्रीय आयोग ₹2 करोड़ से अधिक के मामलों की सुनवाई करता है।

5. विद्युत वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिह्न कौन सा है?
- अगमार्क
 - हॉलमार्क
 - आईएसआई चिह्न
 - एफपीओ चिह्न

(C)

व्याख्या: आईएसआई चिह्न विद्युत वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी देता है।

6. उपभोक्ता की कौन-सी जिम्मेदारी खरीदारी के बाद नकद पर्ची माँगने से संबंधित है?
- पर्यावरण का सम्मान
 - उत्पाद के लेबल पढ़ना
 - नकद पर्ची माँगना
 - ईमानदारी बरतना

(C)

व्याख्या: नकद पर्ची माँगना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिससे बाद में शिकायत के समय प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके।

7. 'जागो ग्राहक जागो' अभियान किस संस्था द्वारा चलाया जाता है?
- राज्य सरकार
 - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
 - उपभोक्ता मामले विभाग
 - टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण

(C)

व्याख्या: उपभोक्ता मामले विभाग 'जागो ग्राहक जागो' अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक करता है।

8. जिला आयोग की अधिकार सीमा क्या है?
- ₹10 लाख तक
 - ₹50 लाख तक
 - ₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक
 - ₹2 करोड़ से अधिक

(B)

व्याख्या: जिला आयोग उन मामलों की सुनवाई करता है जिनका मूल्य ₹50 लाख से अधिक नहीं होता।

9. 'अनुचित व्यापार प्रथा' में क्या शामिल है?
- असली वस्तुओं की आपूर्ति
 - भ्रामक विज्ञापन
 - गारंटी प्रदान करना
 - गुणवत्ता की गारंटी

(B)

व्याख्या: भ्रामक विज्ञापन उत्पाद की गुणवत्ता या विशेषताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और अनुचित व्यापार प्रथा में आता है।

10. उपभोक्ता संगठनों और एनजीओ की भूमिका क्या है?
- छूट पर उत्पाद बेचना
 - केवल अमीर उपभोक्ताओं की सहायता करना
 - उपभोक्ताओं को शिक्षित करना और शिकायत दर्ज करना
 - सरकारी एजेंसियों का स्थान लेना

(C)

व्याख्या: उपभोक्ता संगठन और एनजीओ उपभोक्ताओं को शिक्षित करते हैं और उनके हितों की सुरक्षा हेतु शिकायत दर्ज करते हैं।